

डा. बिनोद कुमार द्विवेदी
सहायक प्रोफेसर
शासिक संकाय
एसपीडी कॉलेज, गढ़वा

भारत में ग्रामीण विकास

भारत गांधी का देश है। इसीलिए भारत के गांधी की दशा का अध्ययन कर इनमें व्याप्त समस्याओं के समाधान का प्रयास ही ग्रामीण विकास कहलाता है। अर्थात् ग्रामीण विकास उस कान्ति को कहते हैं जो ग्रामीण ढांचे को नया रूप प्रदान करे।

ग्रामीण विकास की आवश्यकता एवं महत्व

प्रत्येक राष्ट्र अपनी राष्ट्रीय परंपराओं एवं दिश्याओं के आधार पर भविष्य का रूप निर्धारित करता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भारत के भविष्य का निर्माण करने के लिए ग्रामीण विकास संबंधी योजना का प्रतिवेदन किया था। इसीलिए गांधीवादी प्रयोगों पर आधारित ग्राम विकास आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक स्वतंत्रताओं पर आधारित है। इसमें वर्ग संघर्ष, जातीय विरोध, शिक्षा, शक्ति और संपत्ति के क्षेत्र में प्रगतिशील निर्णय लिये जाने का प्रावधान है। भारत प्राथमिक रूप से एक ग्रामीण देश है और इसकी समृद्धि ग्रामीण क्षेत्रों की समृद्धि पर निर्भर है। इस प्रकार स्वतंत्र भारत की यह प्रथम दिशाधारा है जो ग्रामीण समुदाय के विकास पर केन्द्रित है। हम सभी जानते हैं कि भारत की 80 फीसदी जनसंख्या ग्रामीण है। जबकि कनाडा में 48 प्रतिशत, उत्तरी आयरलैंड में 59 प्रतिशत और फ्रान्स की 51 प्रतिशत जनसंख्या ही ग्रामीण है। इस तरह अन्य देशों की तुलना में ग्रामीण विकास की आवश्यकता इस देश के लिए राष्ट्रीय समृद्धि में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। ग्रामीण विकास एक बहुदेशीय योजना है जिसके अन्तर्गत आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक, स्वास्थ्य संबंधी आदि सभी समस्याओं को संगठित एवं संस्थात्मक तरीके से ग्रामीण विकास के अन्तर्गत ही दूर किया जा सकता है। ग्रामीण विकास उन सुविधाओं, प्रयोगों तथा प्रयत्नों का जाल है जो अपेक्षित परिणाम प्राप्त कर सकता है। ग्रामीण विकास का लक्ष्य ग्रामीण समाज का भौतिक, मानसिक, अध्यात्मिक, सामाजिक एवं आर्थिक विकास है। इस आन्दोलन के द्वारा न केवल ग्रामीण व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाना है बल्कि उसमें आत्मसंतुष्टि, आत्मविश्वास तथा आत्म अभिमान के गुण भी विकसित करना है।

भारत में ग्राम विकास का इतिहास

भारत में ग्राम विकास के लिए प्रत्येक युग में प्रयास होता आया है। ग्राम विकास के आन्दोलन में सदैव आर्थिक एवं सामाजिक परिस्थितियों की छाप रही है। पुरातन काल में गौतम बुद्ध, चन्द्रगुप्त आदि इस क्षेत्र में महान दार्शनिक हो गये हैं। जिन्होंने अपने काल में ग्राम विकास की भावनाएं प्रस्तुत की हैं। मुगल काल से लेकर इतिहास के हर काल में ग्रामीण विकास की ओर प्रत्येक सम्राट और राजा का ध्यान गया है। और इस दिशा में प्रयास हुए हैं। आधुनिक युग में तो ग्रामीण कल्याण भावनाओं में विशेष प्रगति लक्षित होती है। इस प्रकार भारतीय ग्रामों की समस्त समस्याओं का निवारण करने के लिए प्रारंभ से ही प्रयत्न होते आए हैं। देश की आजादी से पूर्व और आजादी के बाद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का ध्यान इस दिशा में सबसे पहले केन्द्रीत हुआ था। ग्रामीण विकास की आकांक्षा उनके प्रत्येक प्रयास में लक्षित होती है।

ग्रामीण विकास में बाधाएं

आजादी के बाद भी हमारे गांव आज भी बहुत अधिक विकसित नहीं हो पाए हैं। इसका मूल कारण यह है कि ग्रामीण समाज आज भी निराशावादी दृष्टिकोण रखता है। अशिक्षित होने के कारण ग्रामीण जनता योजनाओं को समझ नहीं पाती है और परिणाम स्वरूप उनसे लाभ नहीं उठा पाती। ग्रामीण विकास के कार्य में एक सबसे बड़ी बाधा यह भी है कि हमारे गांव में पूर्ण रूपेण जन जागृति नहीं हो पायी है। कुछ योजनाएं तो केवल सरकारी बनकर रह गयी हैं। जनता की योजनाएं नहीं बन पायी हैं।

ग्राम विकास के उद्देश्य

भारत के भविष्यवक्ता एवं महान दार्शनिक महात्मा गांधी ने ग्रामीण विकास के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा था कि अहिंसक समाज में कोई किसी का शत्रु नहीं होगा, सब अपना-अपना काम करेंगे, कोई निस्स्वार्थ नहीं रहेगा, उत्तरोत्तर सबके ज्ञान की वृद्धि होती जाएगी। सारी प्रजा में कम से कम बीमारियां कम होंगी। कोई दरिद्र नहीं होगा और पश्चिम करने वालों को बराबर काम मिलता रहेगा। ग्रामीण विकास के निम्नांकित उद्देश्य निर्धारित किये जा सकते हैं :-

1. ग्रामीण निर्धनता को दूर कर जीवन स्तर को उन्नत बनाना
2. ऋण के दोषों को दूर कर ग्रामीण जनता की आर्थिक उन्नति को उन्नत बनाना
3. कृषि के साधनों व शिधियों में आमूलचूल परिवर्तन करना

4. कुटीर उद्योगों का पुर्नस्थान कर आत्मनिर्भरता की शक्ति प्रदान करना
5. अमदान की भावना जागृत कर स्वयं सेवा के भाव पैदा करना
6. सामुहिक जीवन व्यतीत करने का प्रशिक्षण देकर संगठन की भावना में वृद्धि करना
7. शिक्षा एवं संस्कृति का प्रसार करना
8. जन स्वास्थ्य एवं ग्राम्य स्वच्छता का ज्ञान कराना
9. लोकतांत्रिक भावना उत्पन्न कर स्थानीय शासन की स्थापना करना
10. मनोरंजन एवं सहकारी संस्थाओं की स्थापना करना
11. भूमि व संपत्ति का समान वितरण कर वर्गभेद का निवारण करना
12. जाति-पाति एवं छुआछूत को दूर करना
13. ग्रामीण जीवन को समृद्धशाली बनाना
14. निवास व्यवस्था में यातायात के साधनों की उन्नति करना
15. जन सहयोग द्वारा ग्रामों में आर्थिक उन्नति के कार्यक्रमों को सफलता पूर्वक क्रियान्वित करना

ग्राम विकास के उपर्युक्त उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए कहा जा सकता है कि ग्रामीण विकास का क्षेत्र इतना विस्तृत है कि ग्रामीण संरचना का पूर्ण परिवर्तन, नवस्थापन आदि सदैव से इसके लक्ष्य रहे हैं।

ग्रामीण विकास के क्षेत्र में आने वाले समस्याएं

1. ग्रामीण जनता का निराशावादी दृष्टिकोण
2. गंदगी का साम्राज्य
3. चिकित्सा एवं कुराल दाइयों का अभाव
4. शिक्षा एवं प्रशिक्षण की कमी
5. मनोरंजन एवं साधनों की अद्यवस्था
6. कृषि एवं पशुपालन के दोष
7. बीज एवं सिंचाई के उन्नत साधनों की कमी

8. पशुओं की बीमारियाँ
9. मुकद्दमेबाजी एवं ग्रामीण ऋण व्यवस्था
10. सामाजिक रीति रिवाजों का साम्राज्य
11. पंचायतों का पुर्नगठन
12. बेरोजगारी एवं निर्धनता

तेजी से निरन्तर बदल रही परिस्थियों को दृष्टिगत रखते हुए केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों, सामाजिक एवं राजनैतिक संगठनों आदि का ध्यान अब ग्रामीण विकास पर केन्द्रीत हो गया है। विभिन्न योजनाओं द्वारा ग्रामीण विकास की अध्वारणा को साकार रूप देने का प्रयत्न किया जा रहा है।

ग्रामीण विकास के कार्यक्रम

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् 1 अप्रैल 1951 से नियोजित आर्थिक विकास के माध्यम से ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर बल दिया जा रहा है। भारत में सामाजिक न्याय के साथ प्रगति हो। यह लगभग सभी योजनाओं का मूल उद्देश्य रहा है।

ग्रामीण विकास की कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है

1. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम—इस योजना की शुरुआत 2 फरवरी 2006 को 27 राज्यों के 200 चुने गये जिलों में किया गया। इन 200 जिलों में से 150 जिलों में पूर्ण से ही काम के बदले अनाज योजना कार्यक्रम चल रहा था जिसे नरेगा में विलय कर दिया गया। दिसम्बर 2009 से इस योजना का नाम बदल कर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया।
2. स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना—गरीबों को स्वरोजगार में सहायता करने, कौशल विकास, ऋण अनुदान देने के उद्देश्य से 1 अप्रैल 1999 में इस योजना की शुरुआत की गयी।
3. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना—25 दिसम्बर 2000 से केन्द्र प्रायोजित इस योजना की शुरुआत की गयी। इसके अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क विहीन गांवों में सड़क निर्माण कराना है।

4. इन्दिरा आवास योजना—आवास जैसी बुनियादी आवश्यकता की पूर्ति के लिए वर्ष 1985-86 में इन्दिरा आवास योजना को एक उपयोजना के रूप में प्रारंभ की गयी। इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा मुक्त बंधुआ मजदूरों को नि:शुल्क आवास उपलब्ध कराना है।
5. समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम—बंजर भूमि के विकास से उत्पादकता में वृद्धि के साथ ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार में वृद्धि के लिए वर्ष 1989-90 से इस योजना की शुरुआत की गयी।
6. अन्नपूर्णा योजना—बीपीएल वर्ग की सहायता के लिए इस योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2000 को हुयी।
7. राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना
8. ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं के प्रावधान की योजना
9. जवाहर रोजगार योजना—इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार और अपर्याप्त रोजगार प्राप्त पुरुषों व महिलाओं के लिए अतिरिक्त लाभप्रद रोजगार का सृजन करना है।
10. राष्ट्रीय विस्तार सेवा — इसके अन्तर्गत निम्नांकित कार्य किये जाते हैं—
 - । कर्मचारियों का प्रशिक्षण
 - ॥ प्रचार/प्रसार
 - ॥ कृषक शिक्षण
11. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम

|